



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122024-259096
CG-DL-E-02122024-259096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4788]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2024/अग्रहायण 11, 1946

No. 4788]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2024/AGRAHAYANA 11, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024

का.आ. 5180(अ).— यतः, मै. केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ने केरल राज्य में चीमेनी गांव, होसदुर्ग तालुक, कासरगोड जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 503(अ) दिनांक 28 फरवरी, 2013 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन में 40.4711 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 40.4711 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, केरल सरकार ने उनके पत्र संख्या आईटी-ए2/6/2017-आईटीडी-भाग(1) दिनांक 5 अक्टूबर, 2024 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा और भूमि का टुकड़ा राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 40.4711 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/109/2008-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2024

S.O. 5180(E).—Whereas, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Cheemeni Village, Hosdurg Taluk, Kasaragod District, in the State of Kerala;

AND, WHEREAS, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 40.4711 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 503 (E) dated 28.02.2013;

AND, WHEREAS, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Limited has now proposed to de-notify the entire area of 40.4711 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Kerala has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. IT-A2/6/2017-ITD-Part(1) dated 5th October, 2024. After de-notification, the parcel of land will conform to land use guidelines/ master plan of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 40.4711 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/109 /2008 -SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.